IndeGnitc Strike of Postal Employees

4461. SHRI SANJAY NIRUPAM:
SHRl K.M. KHAN:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI W. ANGOU SINGH:
SHRIMATI SAROJ DUBEY:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether more than six lakhs postal employees were on an indefinite strike from 9th July, 1998;

(b) if so, the details thereof with names of Union participated in it;

(c) whether Government propose to consider demands of these employees;

(d) if so, the details thereof and if not, the steps proposed to be taken to ensure delivery of mail during strike period;

(e) whether Government propose to extend dates of payment of Telephone Bills and Electricity Bills being delivered to subscribervfconsumers by post; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefcfr?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Of the total number of Postal Employees, the strike was resorted to by Postal UnionyAssociations with a total membership of 3.5 lakhs.

(b) A list of the Unions which participated in the strike is enclosed at Statement-I *(See below).*

(c) The demands are under consideration at the appropriate level.

(d) A Committee has been set up comprising Members of Staff side and Officials side to consider the demands of Postal Employees. Serveral steps had been taken by the Department to ensure delivery by mail during strike. Details are given in Statement-II *(See below).*

(e) and (f) As regards extending of dates of payment of Telephone Bills, there is no such proposal at present. However, such general comolaints are examined on merits as and when received.

As regards extending of dates of payment of Electricity Bills, the matter is note related to Ministry of Communications.

Statement-I

Name of the Unions which participated in the Strike.

1. All'India Postal Employees Union, Group 'C.
2. All India RMS & MMS Employees Union, Group 'C.
3. All India Postal Employees Union, Postemen & Class-IV.
4. All India RMS & MMS Employees Union, Mailguards & Class-IV.
5. All India Postal Extra Departmental Employees Union.
6. National Union of RMS & MMS, Group 'C.
7. National Union of Postal Employees, Group 'C.
8. National Union of Postal Employees, Postmen & Group 'D'.
9. National Union of RMS & MMS Employees Mailguards & Group 'D'.
10. National Union of Extra Departmental Agents (Not recognised)
11. AH India Postal Administrative Offices Employees Union Class-Ill & IV.
12. All India Postal Accounts Employees Association.

Statemeat-II

The following arragements were made to ensure delivery of mail to the extent possible, during strike period.

(i) Some Post Offices were identified to run the skeleton services.

(ii) Identified Post Offices were instructed to deliver mail either through Postmen available or at window.

(iii) The mails for Bulk recipients was to be sorted out and delivered through special staff if feasible other wise heads of InstitutesOffices receiving mail in bulk were to be requested to collect their mail at their own.

(iv) Sp>ecial arragements were made to deliver the communication (Admission forms, result sheets etc.) from College^ Universities addressed to students.

(v) Money Orders meant for student were transmitted on VSATESMOFAX network and delivered through special staff.

(vi) Speed Post articles were also delivered in the same nianner.

(vii) The Heads of Circles were authorised to engage outsider including students and retired officials for processing and delivery of mail.

(viii) New recruitsirainies were called for from training and their services were utilised for providing postal services.

(ix) Contractual vehicles were allowed to be utilised for conveyance of mails under Supervision of a responsible departmental official.

दूरसंचार विभाग को निगम के रूप में परिवर्तित किया जाना

4462. **श्रीमती सरोज दुवे**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरसंचार विभाग को निगम के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में भी कोई परिवर्तन किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उपका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ अभरती हुई प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी ठंग से सामना करने के लिए इसकी कार्यकारी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए मुक्यत: नीतिनिर्माण तथा लाइसेसिंग कार्यों के प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने के संबंध में दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) का पुनर्गठन करने के मामले की जांच की जा रही है। पिछले वर्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण की स्थापना को भी नीति निर्माण तथा लाइसेंसिंग कार्यों को प्रचालनात्मक कार्यों से अलग करने की दिशा में एक तर्क संगत कदम माना जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि, कुछ वर्ष पूर्व, भावी प्रचालनात्मक तथा विकासात्मक आवश्यकतओं को ध्यान में रखते हुए देश में दूरसंचार संवाओं के प्रबंध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे के बारे में सिफारिश करने के लिए डा. अभय, एक जाने माने प्रबंध विसेषज्ञ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने (जिसने मार्च, 1991 में अपनी निपोर्ट प्रस्तुत की) किसी भी संशोधित संरचना में "नीति तथा नियमन" टियर को "प्रचालन" (आपरेशन) टियर से अलग करने की आवश्यकता को स्वीकार किया लेकिन समिति इस विभाग के भावी संगठन के आकार के वारे में एकमत नहीं थी।

तदनुसार, 1995 में डीआटा मुख्यालय की पुनसंरचना के बारे में सिफारिश करने के लिए श्री डी.के. गुप्ता, सेवानिवृत संदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान समिति ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारी संषों के प्रतिनिथियों से मुलाकात की और अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि डी ओ टी को दो स्पष्ट रूप से परिभावित निकायों में विभाजित कर दिया जाए एक निकाय नीति तथा योजना तौयार करने के लिए तथा दूसरा दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य करने के लिए जिसे " इंडिया टेलीका म" कहा जा सकता है।

डी के. गुप्ता समिति ने यह भी निफारिश की कि स्वतंत्र मूल्य एवं लाभ केन्द्रों के रूप में सर्किलों/जिलों के साथ-साथ "इंडिया टेलीकाम" को एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इस रिपोर्ट के और आगे जांच की गई और इस बात पर सहमति हुई कि दूरसंचार विभाग के प्राचलन कार्यों को लाइसेंसिंग तथा नीति कार्यों से अलग किया जाए ताकि को डेडिकेटेड मैनेजमेंट इनपुट्स प्रदान किया जा सके तथा सभी दरसचार प्रचालकों को लेवल-प्लेईग फील्ड प्रदान किया जा सके।

हाल के महीनों में, इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न यूनियनों तथा स्टाफ संघोंके साथ चर्चा की गई है। प्रस्तावित पुरसैचना तथा इससे जुड़े जटिल मुद्दों के संबंध में जबकि अनेक विचार एवं मत दिये गये हैं,